



गांव हमारा

चौपाल से
भीपाल तक

भोपाल, सोमवार 03-09 अक्टूबर 1 2022, वर्ष-8, अंक-26

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुँरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

घोटाला: नर्मदापुरम जिले में सात साल में खा गए ढाई सौ करोड़ रुपए

रेशम उत्पादन में लगा भ्रष्टाचार का 'कीड़ा'

» लोकायुक्त-ईओडब्ल्यू में शिकायत के बाद भी नहीं रुका घोटाला

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों को समृद्ध बनाने के लिए रेशम उत्पादन में सरकार कई तरह से मदद कर रही है, लेकिन यह उद्योग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। नर्मदापुरम जिले में सात साल के भीतर तीन अलग-अलग घोटालों में ढाई सौ करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार का अनुमान है। रेशम आयुक्त ने पिछले हफ्ते दो कर्मचारियों को गड़बड़ी के आरोप में निलंबित किया है, लेकिन उन बड़े अधिकारियों पर आंच नहीं आई जिनका काम निगरानी का था। किसानों ने अलग-अलग समय में इसकी शिकायत लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और विभाग के अधिकारियों से की है। इसके बाद भी गड़बड़ी नहीं रुक रही है।

तीनों मामलों में अलग-अलग तरह की गड़बड़ी की गई है। कहीं ज्यादा जमीन में उत्पादन दिखाकर सैंडविच राशि अधिकारियों-कर्मचारियों ने अपनी जेब में डाल ली तो कहीं स्टॉक ही गायब कर दिया। रेशम उत्पादन के लिए घर बनाने में भी शर्तों का पालन नहीं किया गया। रेशम संचालनालय की तरफ से जांच एजेंसियों को दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।



इस प्रकार हुआ घोटाला

घोटाला-1: पहला घोटाला 2015 में सामने आया था। इसकी शिकायत लोकायुक्त में की गई थी। मामले की जांच चल रही है। यह करीब 200 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। इसमें अधिकारियों-कर्मचारियों ने मिलकर शहूत की खेती का रकबा ज्यादा दिखाया था। दरअसल, इसके लिए भारत सरकार से अनुदान मिलता है। इस कारण खेती का ज्यादा क्षेत्र दिखाकर ज्यादा अनुदान लिया गया। दूसरी गड़बड़ी रेशम के कीड़े पालने के लिए बनाए जाने वाले घरों के निर्माण में हुई। घर बनाने में निविदा शर्तों का पालन भी नहीं किया गया। लोकायुक्त पुलिस की तरफ से जांच की आगे बढ़ाने के लिए रेशम संचालनालय से दस्तावेज मांगे गए हैं, लेकिन संचालनालय की तरफ से अभी तक

जानकारी नहीं दी गई है। इस कारण जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। जांच के बाद इस गड़बड़ी का आंकड़ा 200 करोड़ से ऊपर पहुंच सकता है।

घोटाला-2: कंकून (जिससे रेशम का घागा निकलता है) बैक मालाखेड़ी में जितना स्टॉक होना चाहिए उतना नहीं मिला। 11.50 करोड़ रुपए का स्टॉक कम था। 2019 में यह मामले सामने आया था, जबकि गड़बड़ी 2007-08 से शुरू होने के तथ्य मिले हैं। इस मामले की विभागीय जांच चल रही है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में रेशम के वस्त्रों के उत्पादन का भी मिलात किया जा रहा, जिसमें बड़ी गड़बड़ी सामने आ सकती है। किसानों ने जिला रेशम अधिकारी शरद श्रीवास्तव के खिलाफ नामजद शिकायत की थी।

हाल ही में दो कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। विभागीय जांच भी चल रही है। दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है।
मनु श्रीवास्तव,
आयुक्त, रेशम

» रेशम आयुक्त ने पिछले हफ्ते दो कर्मचारियों को निलंबित किया

» बड़े अधिकारियों पर आंच नहीं आई जिनका काम निगरानी का था

कृषि और एनसीएनएफ के बीच एमओयू

प्राकृतिक खेती में मप्र निकला सबसे आगे

भोपाल। जागत गांव हमार

संचालक किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग और अध्यक्ष नेशनल कोएलीशन फॉर नेचुरल फार्मिंग (एनसीएनएफ) के मध्य अधिक प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन हुआ। संचालक कृषि प्रीति मैथिल ने कहा है कि प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने और खेती की लागत में कमी लाकर उनकी आय में वृद्धि करने में एमओयू कारगर साबित होगा। एनसीएनएफ के अध्यक्ष मिहिर शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के 40 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने, जैविक उत्पादन, उचित मूल्य प्राप्त करने जीवाणु, बीजामुन, गोबर की खाद, वर्मी कम्पोस्ट और रोगों एवं कीटों की रोकथाम के लिए जैविक कीटनाशक तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।



किसानों की बढ़ रही आय

प्राकृतिक खेती के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के बेहतर बनाने और भूमि की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। निरंतर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से क्षीण हो रही भूमि की उर्वरा शक्ति, नष्ट हो रहे कृषि मित्र केंचुए और जन्म ले रही मानव जन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रदेश में प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में बेहतर तरीके से कार्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्राकृतिक खेती के रकबे को बढ़ा कर खेती की लागत में कमी लाई जाकर किसानों की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए शासन निरंतर कार्य कर रहा है।

प्राकृतिक खेती में 'पार्टनर' निभाएंगे अहत भूमिका

किसानों को जागरूक करने में एनसीएनएफ समान विचारधारा वाले 23 पार्टनर संस्थाओं के साथ मिल कर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को लाभान्वित करने में अहत भूमिका निभाएंगी। प्राकृतिक खेती के लिए एनसीएनएफ द्वारा नेचर पॉलीटिव एग्रीकल्चर एवं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा शासन के साथ पॉलिसी एवं क्रियान्वयन के स्तर पर भी सशक्त भागीदारी की जाएगी।

अयोध्या के वैज्ञानिकों ने तैयार की आम की नई प्रजाति और नाम रखा नरेंद्र

अब सितंबर माह में भी मिलेगा मीठे-रसीले आम का स्वाद

अयोध्या। जागत गांव हमार

आचार्य नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिकी विवि कुमारगंज के उद्यान व वानिकी विभाग के वैज्ञानिकों ने एक आम से ऐसी प्रजाति का जनन द्रव्य प्राप्त किया है, जिससे मीठा, रसीला, सेहतमंद आम का फल मिलेगा। इसका एक पेड़ भी तैयार कर लिया गया है। इसकी कलम अक्टूबर माह में रोपित की जाएगी। यह दो साल में पेड़ बनकर फल देना लगेगा। कृषि वैज्ञानिकों ने इस आम को नरेंद्र आम-1 नाम दिया है। यह आम सितंबर के अंत तक पककर तैयार हो जाएगा। इस साल अक्टूबर में इसकी प्रजाति रोपित की जाएगी। मीडियम साइज का होने वाला यह पेड़ दूसरे साल आम देने के

लिए तैयार हो जाएगा। वहीं, उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. संजय पाठक की इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विजेंद्र सिंह ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि इससे किसानों को अधिक लाभ मिल सकेगा। कई साल के रिसर्च का परिणाम- इसकी खासियत यह होगी कि यह सितंबर माह में फल देगा जबकि इस माह में कोई आम का फल नहीं तैयार होता। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के उद्यान व वानिकी विभाग के अधिष्ठाता व फल वैज्ञानिक डॉ. संजय पाठक व उनकी टीम ने कई साल के रिसर्च के बाद आम के इस जनन द्रव्य का संरक्षित किया था।



बड़े स्तर पर होगा रोपण

वैज्ञानिकों ने नाम नरेंद्र आम-1 रखा गया है। इसे बड़े स्तर पर वानिकी में रोपित किया जाएगा। बताया कि अभी तक बिहार में पैदा होना वाला फजली आम सबसे लेट वैरायटी का आम माना जाता है, लेकिन अब यह आम उसके बाद ही पैदा होगा।

दशहरी व नीलम के क्रॉस से आग्रपाली व इससे मल्लिका आम का जन्म हुआ है। इसे कृषि विवि की नर्सरी में पैदा किया जा चुका है। अब वृद्ध रोपण की तैयारी है। इस आम का फल 200 से 250 ग्राम तक वजन होता है। इसे काट कर खाया जा सकता है। यह खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। इस वृक्ष के जनन द्रव्य को विकसित कर नई प्रजाति तैयार की गई है। डॉ. संजय पाठक, उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता

पेस्ट फ्री एरिया फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर कार्यशाला में बोली रश्मि

सबसे पहले कृषि और कृषक की नीति अपना रही सरकार

भोपाल। जगत गांव हजार

बेहतर उत्पादन और किसानों को लाभान्वित करने के लिए जरूरी है कि कोटों से फसलों की सुरक्षा बेहतर तरीके से की जाए। फसलों को कोटों से बचाने की जिम्मेदारी कृषि वैज्ञानिकों से लेकर कृषक तक की है। फसलों को कोटों से बचाव कर हम बेहतर उत्पादन और बेहतर इनकम प्राप्त कर सकते हैं। यह बात अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में प्लांट प्रोटेक्शन पेस्ट फ्री एरिया विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला में प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर फरीदाबाद डॉ. जेपी सिंह ने कही। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की प्रबंध संचालक जीव्ही रश्मि ने कहा कि राज्य सरकार कृषि और कृषक सबसे पहले की नीति पर कार्य कर किसानों को लाभान्वित कर रही है। एमडी मंडी बोर्ड रश्मि ने कहा कि राज्य शासन द्वारा गेहूं निर्यात को प्राथमिकता दी गई है।

मग्न में नहीं करना बंट बीमारी

कार्यशाला में जानकारी दी गई कि मध्यप्रदेश में करनाल बंट बीमारी का कोई भी प्रकरण अभी तक नहीं आया है। विदेशों में मध्यप्रदेश में उत्पादित गेहूं की अत्यधिक मांग है। करनाल बंट फ्री सर्टिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा प्रमाणिकता के आधार पर जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की मिट्टी तथा जलवायु करनाल बंट के वायरस को पनपने नहीं देती है।

यह रहे मौजूद

एचओडी प्लांट पैथोलॉजी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जबलपुर जयंत भट्ट, आईआईडब्ल्यूबीआर प्रिंसिपल साइंटिस्ट करनाल सुधीर कुमार, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन फरीदाबाद ओपी वर्मा सहित वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कृषि अधिकारी मौजूद रहे। कृषि विपणन बोर्ड के अपर संचालक (निर्यात) डीके नागद ने आभार माना।

गेहूं निर्यात में हम नंबर वन

प्रदेश गेहूं निर्यात के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में सकल निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश स्टेट कॉउंसिल का भी गठन किया गया है। कृषि और कृषक सबसे पहले की नीति पर प्रदेश में फार्म गेट एम्प प्रारंभ कर किसानों को उनके खेत एवं खलिहान से ही उपज के विक्रय का अधिकार एवं साधन उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उपज के रख-रखाव और परिवहन में होने वाले समय की बचत की जा सकेगी। कार्यशाला करनाल बंट की रोकथाम पर केंद्रित रही। वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की फसल में लगने वाले कीट करनाल बंट से बचाव के उपाय बताए गए। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के आधार पर करनाल बंट बीमारी की रोकथाम मध्यप्रदेश में किस तरह की जा सकती है, की जानकारी दी।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया शिलान्यास

अभयारण्य क्षेत्र से रेत उपलब्धता स्थानीय स्तर पर बढ़ेंगे रोजगार

मुरैना में जैविक बीज फार्म का 'श्रीगणेश'

-मंडी बोर्ड में ढाई साल में दी गई 156 नियुक्तियां

सर्वोच्च प्राथमिकता से दी अनुकंपा नियुक्ति

भोपाल। जगत गांव हजार
किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान हम से बिछड़ गए मंडी बोर्ड के कर्मचारियों के निकटस्थ आश्रितों को सर्वोच्च प्राथमिकता से नियुक्तियां दी गई हैं। उन्होंने बताया कि मंडी बोर्ड में 13 परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति सह-सहमति पत्र प्रदान किए गए हैं। मंत्री ने बताया है कि मार्च 2020 में सरकार बनने के बाद से मंडी बोर्ड में आज तक मंडी बोर्ड में कार्यरत रहे हुए दिवंगत हुए 156 अधिकारी-कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की है। कृषि मंत्री ने नवनियुक्त मंडी बोर्ड के कर्मचारियों से कहा कि वे अपने परिवारों का सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह करेंगे। उन्होंने अपेक्षा की



- » 207 हेक्टेयर भूमि के डी-नोटिफिकेशन का निर्णय
- » बीज फार्म से किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज मिलेंगे, आय बढ़ेगी



भारत की साख दुनिया में बढ़ी

तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में चौरफा काम होने से भारत की साख दुनिया में बढ़ी है। हमारा देश वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से कार्य कर रहा है। पीएम का नारा है जय जवान, जय किसान जय विज्ञान, जय अनुसंधान, मुरैना का बीज फार्म किसानों की प्रगति के लिए विज्ञान व अनुसंधान का पूरा उपयोग करेगा। बीज कृषि का आधार व प्रमुख आदान है। खेती के लिए अच्छे बीजों की उपलब्धता से उत्पादकता में वृद्धि और किसानों के लिए उच्च आय के अलावा एग्री इको-सिस्टम व अर्थ-व्यवस्था को समग्र रूप से लाभ होता है।

बीज उत्पादन की तकनीक सिखाएंगे
एनएससी के विशेषज्ञों द्वारा स्थानीय और प्रदेश के किसानों को ट्रेनिंग के जरिये नवीनतम बीज उत्पादन तकनीक सिखाई जाएगी। मुरैना के स्थानीय श्रमिकों को फार्म में भूमि सुधार एवं बीज उत्पादन से रोजगार प्राप्त होगा। मुरैना फार्म से किसानों को नवीनतम एवं आनुवंशिक व भौतिक रूप से शुद्ध जैविक तिलहन बीज प्राप्त होने से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा, जिससे न केवल प्रदेश के कृषकों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार होगा, बल्कि कृषकों को पोषण सुरक्षा भी प्राप्त होगी।

रोपण सामग्री सब मिशन लागू
केंद्र सरकार, राज्यों में बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विविध योजनाओं द्वारा बीज वितरण में सहायता करती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने फसलों के गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन और गुणन बढ़ाने के लिए 2014-15 से बीज और रोपण सामग्री सब मिशन लागू किया है, ताकि किसानों को पर्याप्त बीज मिले। बीज संबंधी विभिन्न गतिविधियों के जरिये राज्यों व सार्वजनिक क्षेत्र के बीज संगठनों को, बीज गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत किया जा रहा है।

304 किसान अधिसूचित
बीते 8 साल में व्यावसायिक खेती के लिए 304 किसान अधिसूचित की गई हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्य-जीव अभयारण्य क्षेत्र में डी-नोटिफिकेशन से होंगे। तोमर ने डी-नोटिफिकेशन किए जाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से आग्रह किया था। तत्संबंधी प्रस्ताव पर मंत्री यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 69वीं बैठक में चर्चा की गई और समिति ने अभयारण्य से निम्नानुसार 207.05 हेक्टेयर क्षेत्र बाहर करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।

भोपाल। जगत गांव हजार
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया। इसके प्रारंभ होने पर मध्यप्रदेश के किसानों को तिलहन के नए जैविक बीज उपलब्ध होंगे। इस फार्म से किसान आधुनिक पद्धतियों से अवगत होंगे। उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य की 207 हेक्टेयर भूमि डी-नोटिफिकेशन करने की अनुशंसा का बड़ा फैसला लिया है। यह अभयारण्य क्षेत्र राजस्थान भूमि होने से रेत की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर होने से रोजगार भी बढ़ेंगे। तोमर ने बताया कि केंद्र सरकार ने मुरैना में जैविक बीजों के उत्पादन के लिए बीहड़ क्षेत्र में भूमि सुधार कर फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मग्न सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्रालय को मुरैना के 4 गांवों गडोरा, जाखोना, रिठौरा खुर्द, गोरखा में 885.34 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है। चंबल क्षेत्र का बीहड़ होने से कृषि कार्य नहीं हो पा रहा था। एनएससी किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और 15 लाख क्विंटल गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीज उत्पादित कर किसानों को उपलब्ध करा रहा है।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय को जन्म

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मुरैना में जैविक बीजों के उत्पादन के लिए फार्म विकसित करने की जिम्मेदारी एनएससी को सौंपी है। मुरैना में रेवांडस क्षेत्र में बीज उत्पादन से भूमि में सुधार होगा व भूमि उपजाऊ होगी। स्थानीय किसान भूमि सुधार से प्रेरित होकर अपने खेतों में भी भूमि सुधार कर नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति से बीज उत्पादन कर खेती में कम लागत से उच्च आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कृषकों को यहां बीज उत्पादन की नवीनतम तकनीक सीखने की मिलेगी।

भूत्य-चौकीदार के 5 पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की उपाध्यक्ष मंजू दादू, बोर्ड की प्रबंध संचालक-सह आयुक्त जीव्ही रश्मि ने भी नव-नियुक्त कर्मचारियों को बेहतर कार्य की अपेक्षा के साथ शुभकामनाएं दी।

जबलपुर में धान भंडारण में 31.29 करोड़ की हेराफेरी

भोपाल। प्रबंध संचालक वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन दीपक सक्सेना ने बताया कि कॉर्पोरेशन की जबलपुर जिले की शहपुरा शाखा अंतर्गत रघुवीरश्री गोदाम के भौतिक सत्यापन में एक करोड़ 31 लाख 29 हजार 144 रुपए की धान की बोरियां कम पाई गई थी। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक वेयर हाउसिंग जबलपुर को रघुवीरश्री गोदाम के संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त भागीदारी योजना में विभागीय निरीक्षण दल द्वारा गोदाम का भौतिक सत्यापन 11 सितम्बर, 2022 को किया गया।

धान के स्थान पर रखी गई गेहूं की बोरियां

गोदाम में गेहूं, धान, चना, मूंग एवं अरहर की दाल भंडारित की गई थी। सत्यापन में गेहूं की 190 बोरियां अधिक और धान की 16 हजार 919 बोरी एवं चने की 31 बोरी कम पाई गई। इस प्रकार 6 हजार 767 क्विंटल धान कम पाई गई। प्रबंध संचालक द्वारा हेराफेरी का मामला सामने आने पर गोदाम संचालक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण मानते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

मध्यप्रदेश गौ-संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरि ने किया दावा

सेवा पखवाड़ा में गौशालाओं में लग रहे पशु स्वास्थ्य शिविर

लंपी मुक्त गौशालाएं

भोपाल। जागत गांव हमार

राज्य गौ-संवर्धन बोर्ड की कार्य-परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने कहा कि पड़ोसी राज्य राजस्थान और गुजरात में लंपी चर्मरोग फैलने की जानकारी मिलते ही प्रदेश की गौशालाओं में दो माह पूर्व से ही पशु स्वास्थ्य शिविर और टीकाकरण प्रारंभ कर दिए गए थे। यही कारण है कि देश की सर्वाधिक गौशाला वाले मध्यप्रदेश की किसी भी गौशाला में एक भी लंपी चर्मरोग प्रभावित पशु नहीं है। लंपी की चुनौती बड़ी है, परंतु पहले से जारी प्रयासों और सतर्कता बरतने के चलते मध्यप्रदेश हतोत्साहित नहीं है। गिरि ने सेवा पखवाड़ा में भोपाल की महामृत्युंजय गौशाला में पशु स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता, टीकाकरण कार्यक्रम में उक्त बात कही।

अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी जेएन कंसोटीया, संचालक डॉ. आरके मेहता, गौशाला संचालक व्यास, प्रशासनिक अधिकारी, जन-प्रतिनिधि, पशु चिकित्सक और बड़ी संख्या में गौ-सेवक मौजूद थे।

खाली गौशाला में करें क्वारेटाइन

अखिलेश्वरानंद ने कार्यक्रम में मौजूद अतिरिक्त कलेक्टर दिलीप यादव से कहा कि सड़कों पर बैठने वाले अनेक पशुओं में लंपी का प्रकोप देखा गया है। ऐसे पशुओं को मनरेगा के तहत बनने वाली खाली गौशालाओं में क्वारेटाइन कर इलाज की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, ताकि अन्य पशुओं में यह रोग न फैले। गिरि और अपर मुख्य सचिव कंसोटीया ने सेवा पखवाड़े के दौरान निर्धारित कार्यक्रम में गौशालाओं में साफ-सफाई, रंग-रोगन अभियान का भी शुभारंभ किया। अपर मुख्य सचिव कंसोटीया ने कहा कि सेवा पखवाड़ा में प्रदेश की गौशालाओं में गौसेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें गौ-पूजन, गौशालाओं में गायों को गुड़, हरा चारा, लाप्सी का सेवन, पशु उपचार, साफ-सफाई, रंग-रोगन के लिए श्रमदान, पंचगव्य आधारित गौ-उत्पादों के क्रय-विक्रय के लिए स्टाल लगाना और उत्पादों का व्यापक प्रचार-प्रसार, गौशालाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए पंचगव्य आधारित उत्पाद और गौवंश की महत्ता पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।



राज्य गौ-संवर्धन बोर्ड की कार्य-परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की केन्द्रीय कारागारों में संचालित गौ-शालाएं काफी अच्छी अवस्था में हैं। इन गौ-शालाएं की व्यवस्थाएं प्रशंसनीय इसलिए भी हैं कि यहां मेनपावर के साथ आवश्यक राशि की उपलब्धता रहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वे गौ-शालाएं, जिनका संचालन धर्माचार्य साधु-संतों के मार्ग-दर्शन और गौ-भक्तों के आर्थिक सहयोग से हो रहा है, काफी अच्छी स्थिति में हैं। भोपाल जेल की गौ-शाला में 411 गौवंश हैं। इसमें 60 गाय से अच्छी मात्रा में दुग्ध उत्पादन मिल रहा है।

गौशाला को दें दान

स्वामी अखिलेश्वरानंद ने लोगों से आह्वान किया कि वे गाय के निमित्त रोज 10 रुपए निकालें। यह राशि एक साल में 3600 रुपए हो जाएगी, जिसे बोर्ड के पोर्टल पर दान दे सकते हैं। अगर प्रदेश के ऐसे एक करोड़ लोग राशि देते हैं तो वह 3 हजार 650 करोड़ रुपए हो जाएगी। इससे प्रदेश में गौ-स्थिति का परिदृश्य ही बदल जाएगा और देश के लिए भी एक आदर्श मार्गदर्शन बन सकता है। उन्होंने कहा कि वह अपना मासिक मानदेय गौशाला को दान देते हैं।

इन्हें किया सम्मानित। कार्यक्रम में गौ-सेवक शंकर बंजारा, महेश सराठे और तखत सिंह को उच्च कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कोकता और आगर-मालवा के मौजूद पार्षदों ने अपने अनुभव साझा किए और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कार्यक्रम का संचालन डॉ. विनीत तिवारी ने और आभार डॉ. अजय रामटेके ने किया।

कैदियों को गौ

आधारित प्रशिक्षण दें

अखिलेश्वरानंद ने गौ संगोष्ठी में भारतीय गौ-वंश का महत्व, गौसेवा से इहलोक-परलोक की प्राप्ति, सनातन धर्म में आदिकाल से गौसेवा के लाभ आदि की जानकारी दी। उन्होंने जेल प्रशासन से कहा कि गायों से प्राप्त गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, मूछ, घी से पंचगव्य औषधियां तैयार की जा सकती हैं। बंदियों को गौ आधारित लघु उद्योग का प्रशिक्षण दें। उन्होंने आग्रह किया कि जेल परिसर की गौ-शाला में बंदियों के लिए एक अनुसंधान शाला और गौ उत्पादों की प्रयोग शाला बनाएं। गौ आधारित उत्पादों का प्रशिक्षण प्राप्त बंदी मुक्त होने के बाद उद्यमी बन कर आत्म-निर्भर हो सकते हैं।

कृषि मंत्री कमल पटेल बोले-मौके पर भर रहे फार्म

पात्रताधारियों का घर-घर सर्वे कर दिया जा रहा लाभ

भोपाल। जागत गांव हमार

किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं में पात्रताधारियों को लाभांशित करने घर-घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरदा जिले में शुरू किये गये आपकी समस्या का हल-आपके घर अभियान को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सराहा है। अब मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान प्रदेश में पात्रताधारियों को लाभांशित करने के लिए 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। गत दिवस हरदा जिले के खिरकिया में



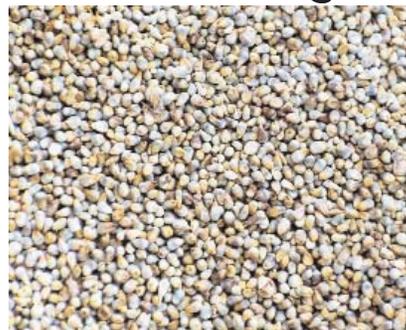
अभियान में विभिन्न योजनाओं के पात्रताधारियों को लाभ प्रदान किए गए। कृषि मंत्री ने कहा कि अभियान में सर्वे दलों द्वारा घर-घर जाकर केन्द्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से वांचित रह गये पात्रताधारियों को चिन्हकित किया जा रहा है। मौके पर ही फार्म भरे जा रहे हैं। मौके पर नहीं मिलने वाले पात्रताधारियों के फार्म शिविरों में भरे जाकर लाभ पहुंचाया जा रहा है। अब पात्रताधारियों को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी-कर्मचारी स्वयं घर आकर लाभ पहुंचाएंगे।

किसानों को फिर समर्थन मूल्य मिलाने पर संकट, अंकुरित हो रही बाजरे की बालियां, दाने भी खराब

प्रदेश में बारिश से बाजरे की गुणवत्ता खराब

भोपाल। जागत गांव हमार

ग्वालियर-चंबल अंचल सहित प्रदेश के कई जिलों में सितंबर में हुई वर्षा ने बाजरा की फसल को बर्बाद कर दिया है। खड़ी फसल से लेकर कटकर खेत व खलिहान में रखी बाजरा की बालियां अंकुरित होने से दानों की गुणवत्ता खराब हो गई है। ऐसे में इस बार भी किसानों को समर्थन मूल्य पर बाजरा की उपज बेचना मुश्किल लग रहा है। मुरैना जिले में इस बार पिछले बार की अपेक्षा 13 हजार हेक्टेयर अधिक एक लाख 77 हजार हेक्टेयर में बाजरा की खेती हुई है। फसल भी अच्छी थी, लेकिन पिछले दिनों वर्षा के पानी में कई दिनों तक डूबे रहे बाजरा की बालियों के दाने अंकुरित हो गए हैं। पकी हुई फसल का दाना काला पड़ गया है। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए बाजरा की गुणवत्ता की जांच एफएन्यू (फाइन एक्वेज क्वालिटी) मानक से होती है। इसमें बाजरा का दाना छोटा होना, चमक कम होने और उपज में कुछ और चीज की मिलावट होने पर खरीद नहीं होती। ऐसे में किसानों को चिंता सता रही है कि इस बार भी बाजरा की फसल कहीं समर्थन मूल्य पर बिकने से न रह जाए।



पिछले साल नहीं बिक था बाजरा

पिछले साल भी वर्षा होने से दाने की चमक कम रह गई थी और कोले धब्बे आ गए थे। यह बाजरा समर्थन मूल्य पर पास नहीं हो सका। बाजरा बेचने के लिए 39102 किसानों ने पंजीयन करवाया था, लेकिन

एक भी किसान का बाजरा सरकार ने नहीं खरीदा। 226 किसानों का 1682 मीट्रिक टन बाजरा सोसायटियों ने खरीद भी लिया था, उसे भी एफसीआइ (भारतीय खाद्य निगम) ने फेल कर दिया।

15 अक्टूबर तक पंजीयन

मजबूरी में किसानों को समर्थन मूल्य 2250 रुपए फिटल से काफी कम 1500 रुपए फिटल के भाव में व्यापारियों को बेचना पड़ा। इस बार समर्थन मूल्य पर बाजरा का भाव 2350 रुपए फिटल है। 700 से ज्यादा किसानों के पंजीयन हो चुके हैं, जिनका 15 अक्टूबर अंतिम तिथि तक 42 हजार से ज्यादा रहने का अनुमान है। समर्थन मूल्य पर उन्हीं किसानों का बाजरा खरीदा जाएगा जो एफएन्यू मानक पर पास होंगे। हाल ही में हुई वर्षा से बाजरा की फसल प्रभावित हुई है, जिसका असर समर्थन मूल्य पर खरीदी पर पड़ने की आशंका है। अरुण कुमार जैन, जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, मुरैना

नकली एवं मिलावटी उर्वरक: कैसे करें पहचान

» उमेश कुमार
» रोहित कुमार,
» प्रगति पांडेय
» रोहित कुमार जायसवाल
-मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विज्ञान विभाग, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारागंज, अयोध्या (उ.प्र.)

किसान भाइयों के लिए उर्वरकों में नकली व मिलावटी की एक जटिल समस्या है। खेतों में प्रयोग लाए जाने वाले कृषि निवेशकों में सबसे महंगी सामग्री रासायनिक उर्वरक है। उर्वरकों की शीर्ष उपयोग की अवधि हेतु खरीद एवं रबी के पूर्व उर्वरक निर्माता फेक्ट्रियों तथा विक्रेताओं द्वारा नकली व मिलावटी उर्वरक बनाने एवं बाजार में उतारने की कोशिश होती है। इसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ता है। इसलिए उर्वरकों का सही पहचान करने के लिए किसानों के पास एक जटिल समस्या है। नकली व मिलावटी उर्वरकों की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई रोक अधिनियम लगाए हैं।

किसान भाइयों को उर्वरक की खरीददारी करते समय उर्वरकों की शुद्धता मोटे तौर पर परख लें जैसे- बीजों की शुद्धता बीज को दांतों से दबाने पर कट्ट एवं किच्य की आवाज से, कपड़े की गुणवत्ता उसे छूकर या मसल कर, दूध की शुद्धता उसे उंगली से टपकाकर तथा घी की शुद्धता दानेदार का अनुभव करके पहचान करते हैं। कृषकोंके बीच प्रचलित उर्वरकों में से प्रायः यूरिया, डी ए पी, सुपर फास्फेट, म्यूरेट आफ पोटाश तथा जिंक सल्फेट नकली व मिलावटी रूप में बाजार में उतारे जाते हैं। खरीददारी करते समय किसान भाई इसके प्रथम दृष्टया परख निम्न सरल विधि से कर सकते हैं और प्रथम दृष्टया उर्वरक नकली पाया जाने पर इसकी जांच किसान सेवा केंद्र पर उपलब्ध टेस्टिंग किट से की जा सकती है। टेस्टिंग किट किसान सेवा केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ऐसी स्थिति में विधिक कार्यवाही किए जाने हेतु इसकी सूचना जनपद के कृषि उप निदेशक [प्रसार], जिला कृषि अधिकारी एवं कृषि निदेशक को दी जा सकती है।

यूरिया: यह एक कार्बनिक योगिक है। जिसका उपयोग किसान भाई नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करते हैं। यूरिया में 46.6% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया को पौधों के जीवन का मूल घटक कहा जाता है।

पहचानने की विधि: 1. दाना सफेद, चमकदार तथा गोलाकार होते हैं। 2. पानी में पूरी तरह से घुल जाना और छूने पर शीतल की अनुभूति शुद्धतम का प्रारूप है। 3. गर्म तवे पर रखने से दाना पिघल जाता है, आग को तेज कर दिया जाए तो कुछ नहीं बचता।

डीएपी (डब्लू अमोनियम फास्फेट): डीएपी का प्रयोग किसान भाई मुख्य रूप से फास्फोरस की पूर्ति के लिए करते हैं। डीएपी में 18प्रतिशत नाइट्रोजन तथा 46प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस पौधों के जड़े बनाने में विशेष योगदान रखता है।

पहचानने की विधि: 1. सख्त दानेदार, भूरा, काला, बादामी रंग, नाखूनों से आसानी से छटता है। 2. डीएपी के कुछ दानों को हाथ में लेकर तंबाकू की तरह चूना मिलाकर रगड़ा जाए तो उसमें बहुत तेज अमोनिया जैसी गंध आती है, जिसे सूंघना असहनीय हो जाता है। 3. तवे पर गर्म आग



में गर्म करने पर दाने फूल जाते हैं।
सुपर फास्फेट: यह पौधों को फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए दी जाती है। सुपर फास्फेट बाजार में 3 ग्रेड पर उपलब्ध है - सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट जिसमें क्रमशः 16, 32, 48प्रतिशत फास्फोरस उपलब्ध होते हैं।
पहचानने की विधि: यह सख्त दानेदार, भूरा, काला, बादामी रंगों से युक्त तथा नाखूनों से आसानी से टूटने वाली उर्वरक है और यह पाउडर के रूप में भी मिलता है। इसके

दाने को यदि गर्म किया जाए तो इस के दाने फूल जाते हैं।
एम ओ पी (म्यूरेट आफ पोटाश): म्यूरेट आफ पोटाश पौधों की पोटेशियम की आपूर्ति को पूरा करता है। म्यूरेट आफ पोटाश में 60प्रतिशत पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम को गुणवत्ता तत्व भी कहते हैं क्योंकि पोटेशियम दानों के गुणवत्ता में भाग लेता है।
पहचानने की विधि: 1. पोटाश की असली पहचान इसका कड़ुकार, सफेद कड़ुका, पिसे नामक तथा मिर्च जैसा मिश्रण होता है। 2. पोटाश के दानों को अगर आपस में नम करने पर यदि दाना आपस में नहीं चिपकते हैं तो समझ लें कि यह असली पोटाश है। 3. पानी में घोलने पर अगर इसका लाल भाग पानी के ऊपर तैरने लगे तो समझ लें कि पोटाश असली है।

जिंक सल्फेट: पौधों को जिंक की आपूर्ति के लिए दिया जाता है जिंक सल्फेट में जिंक 21प्रतिशत पाया जाता है। पौधों में फास्फोरस की स्थानांतरण में मुख्य रूप से भाग लेता है।

पहचानने की विधि: जिंक सल्फेट में प्रमुख रूप से मिलाया जाने वाला रसायन मैग्नीशियम सल्फेट है, जोकि जिंक सल्फेट के समान ही होता है इसलिए इसका पहचान करने में कठिनाई होती है। जिंक सल्फेट के घोल में पतला कार्बिक का घोल मिलाने पर सफेद मटमैला मांड जैसा घोल बन जाता है। जिसमें गाढ़ा कार्बिक का घोल मिलाने पर अवक्षेप पूरी तरह घुल जाता है जबकि जिंक सल्फेट के स्थान पर मैग्नीशियम सल्फेट हो तो अवक्षेप पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा। जिंक सल्फेट की असली पहचान यह है कि इस के दाने हल्के सफेद, पीले तथा बारीक कण के आकार के होते हैं। यदि डीएपी के घोल में जिंक सल्फेट मिला दिया जाए तो थपकेदार घना अवक्षेप बन जाता है जबकि मैग्नीशियम सल्फेट मिलाने पर ऐसा नहीं होता है। किसान भाइयों को उर्वरक खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें- उर्वरक खरीदते समय उस पर अंकित वजन करा लेना चाहिए।

रैबीज एक घातक रोग, उपचार से बचाव/रोकथाम बेहतर

» डॉ भवना गुप्ता
» डॉ रणविजय सिंह
» डॉ रश्मि कुलेश
» डॉ. ब्रजमोहन सिंह धाकड़
» डॉ शिवानी मुंडोतिया
-पशु जन स्वास्थ्य एवं महामारी विभाग पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, जबलपुर
-नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (म.प्र.)

पूरे विश्व में 28 सितम्बर को विश्व रैबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस बीमारी की रोकथाम हेतु सबसे पहली वैक्सीन महान वैज्ञानिक लुईस पास्वर द्वारा 1985 में बनाई गई और उनकी याद में तथा जनमानस में रैबीज के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। इसके बचाव के लिए टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण है तथा मनुष्यों में इस बीमारी की रोकथाम हेतु हमें इस बीमारी को कुत्तों/पशुओं में रोकना होगा, भारत में यह बीमारी मुख्य रूप से कुत्ते के काटने से फैलती है। अतः कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ कुत्तों का टीकाकरण, पंजीकरण, आम जन में जागरूकता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी उद्देश्य से पूरे विश्व में 28 सितम्बर को विश्व रैबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस बीमारी की रोकथाम हेतु सबसे पहली वैक्सीन महान वैज्ञानिक लुईस पास्वर द्वारा 1985 में बनाई गई और उनकी याद में तथा जनमानस में रैबीज के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें एवं साधनार्थियों जो की हमें कुत्ते के काटने पर रखनी चाहिए वो इस प्रकार हैं...

जूनोटिक महत्व की बीमारियों में रैबीज एक महत्वपूर्ण बीमारी है। यह एक विषाणु जनित रोग है एवं मुख्य रूप से कुत्तों से या जंगली जानवरों के काटने/खरोंचने से मनुष्यों को फैलता है, इसका विषाणु संक्रमित पशुओं की लार से स्वस्थ पशु और मनुष्यों को फैलता है। आकड़ों के अनुसार भारत में प्रति वर्ष लगभग 20- हजार व्यक्तियों की मृत्यु रैबीज के कारण होती है, जिनमें से ज्यादातर बच्चे हैं, यह एक बहुत प्राचीन बीमारी है, किन्तु हम अभी तक इसका उपचार नहीं ढूँढ सके हैं। इसके बचाव के लिए टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण है तथा मनुष्यों में इस बीमारी की रोकथाम हेतु हमें इस बीमारी को कुत्तों/पशुओं में रोकना होगा, भारत में यह बीमारी मुख्य रूप से कुत्ते के काटने से फैलती है। अतः कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ कुत्तों का टीकाकरण, पंजीकरण, आम जन में जागरूकता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी उद्देश्य से पूरे विश्व में 28 सितम्बर को विश्व रैबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस बीमारी की रोकथाम हेतु सबसे पहली वैक्सीन महान वैज्ञानिक लुईस पास्वर द्वारा 1985 में बनाई गई और उनकी याद में तथा जनमानस में रैबीज के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें एवं साधनार्थियों जो की हमें कुत्ते के काटने पर रखनी चाहिए वो इस प्रकार हैं...



कुत्ते के काटने पर क्या सावधानी बरतें
1. काटने से हुए घाव को बहते हुए पानी एवं साबुन से कम से कम 15-20 मिनट तक धोएं।
2. तुरंत चिकित्सक की सलाह लें एवं टीकाकरण शुरू करावाएं।

3. यदि संभव हो तो जिस जानवर ने काटा है, उसकी निगरानी करें तथा उसे 10-12 दिन तक देखें की कहीं उसमें रैबीज के लक्षण जैसे पागलपन, आक्रामकता, सभी को काटने की प्रवृत्ति या पेरालिसिस आदि इसके साथ साथ बहुत ज्यादा मात्रा में लार का रिसाव तो नहीं हो रहा है।
4. यदि दुर्घात पशु को कुत्ते ने काटा है तब भी पशु का पोस्ट बाइट टीकाकरण करे तथा दूध की अच्छी तरह उबालकर ही पिएं।
5. यदि आपने कुत्ते को पाला है तो उनका टीकाकरण समय समय पर करवाएं इस तरह से आप अपनी एवं अपने परिवार के साथ साथ अपने पालतू एवं समाज की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
6. यदि किसी ने पालतू रवाना रख रखा है तो परिवार के सदस्यों को भी प्रोफाइलेक्टिक टीकाकरण करवाना चाहिए।

कुछ करने से बचें-जैसे
1. किसी भी तरह की झाड़ फूंक आदि से बचना चाहिए।
2. घाव पर हल्दी, तेल, मिर्ची आदि नहीं लगानी चाहिए।
3. घाव में टांके नहीं लगाया जाना चाहिए यदि आवश्यक हो तब भी एक से दो टीके (पोस्ट बाइट) के बाद ही टांके लगवाएं।
4. बिना किसी देरी के चिकित्सक की सलाह जरूर ले तथा डॉग बाइट का इलाज भी डब्ल्यूएचओ के द्वारा निर्धारित केटेगरी के हिसाब से शुरू करना चाहिए। यहां पर वैक्सीन के सही प्रभाव के लिए यह भी आवश्यक है की उसे रखने में कोल्ड चैन को मॉटेन किया गया हो। इस तरह सामाजिक जागरूकता के साथ संयुक्त प्रयास से ही रैबीज से लड़ा जा सकता है।

गांधी जयंती पर विशेष: पर्यावरण को बचाने में आज भी गांधी के विचार प्रासंगिक

पर्यावरण और इससे जुड़ी चिंताएं आज के समय जितनी उग्र रूप में नहीं थीं, लेकिन गांधी ही थे, जिन्होंने भविष्य की चिंताओं को भांपते हुए समाधान सुझा दिया था। 20वीं सदी में जन्म लेने वाले मोहनदास करमचंद गांधी 20वीं सदी में महात्मा बने और अपने विचारों से दुनिया को प्रभावित किया। आज 21वीं सदी में भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं। गांधी के समय में पर्यावरणवाद और इससे जुड़ी चिंताएं आज के समय जितनी उग्र रूप में नहीं थीं, लेकिन गांधी ही थे, जिन्होंने भविष्य की चिंताओं को भांपते हुए समाधान सुझा दिया था। गांधी को पर्यावरणवाद से पहले का पर्यावरणविद कहा जा सकता है। यह सही है कि गांधी जब तक थे, तब पर्यावरण की प्रति इतनी व्यापक चिंता नहीं थी और दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर अलग से कोई आंदोलन नहीं चल रहा था। लेकिन कई मौकों पर गांधी ने पर्यावरण को लेकर सीधी टिप्पणियां की, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांधी भविष्य में पर्यावरण के खतरों से बाकिथ थे। महात्मा गांधी ने स्वच्छता को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाया था और स्वच्छता, पर्यावरण को बेहतर बनाने की पहली सीढ़ी है। उनके भाषणों में पर्यावरण और पारिस्थितिकी जैसे शब्द नहीं दिखते, लेकिन यह भी सही है कि गांधी दर्शन से ही पर्यावरण के प्रति समझ विकसित होती है। यह सर्वविधित है कि पर्यावरण बचाने के लिए भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में जितने भी आंदोलन हुए, उन्होंने गांधीवाद को ही अपना हथियार बनाया और यह सही ही है कि प्रकृति को बचाने के लिए गांधीवाद ही असली औजार है। महात्मा गांधी ने बेहतर भारत के निर्माण के लिए 18 रचनात्मक कार्यक्रमों की परिचयना की थी। अगर इन्हें ध्यान से देखिए तो पाएंगे कि गांधी के यह कार्यक्रम पर्यावरण की बेहतर की लिए थे। उन्होंने आश्रम संकल्प के लिए भी 11 संकल्प लागू किए थे। अगर आप पर्यावरण के लिए किसी को दोषी ठहराना चाहें तो पाएंगे कि हमारी अतीतनी इच्छा को ठहरा सकते हैं। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। गांधी हमेशा अपनी इच्छाओं को काबू करने की बात करते थे।





जिले 248 गांवों के 11 हजार 221 किसान हुए प्रभावित

अतिवृष्टि की सर्वे रिपोर्ट से हुआ बर्बादी का खुलासा

रायसेन में 17 करोड़ 94 लाख की फसल बर्बाद

किसानों को अब राहत ही सहारा

रायसेन। जागत गांव हमार

21 और 22 अगस्त को हुई अतिवृष्टि से जिलेभर के कई इलाकों में बाढ़ आ गई थी। बेतवा, नर्मदा व बीना नदियों में बाढ़ आने से किसानों की फसल पानी में डूब गई थी। कई गांवों में तो पानी फसलों को अपने साथ बहा ले गया था। जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा था। इस नुकसान का आकलन करवाने के लिए जिला प्रशासन ने राजस्व और कृषि विभाग के अमले को खेतों में भेजकर उसका सर्वे कराया था। जिलेभर के 248 गांवों में 468 दलों ने पहुंच कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट सर्वे दल द्वारा जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार जिलेभर में 12982.698 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल को नुकसान पहुंचा है। अतिवृष्टि से जिले के 11221 किसानों की 17 करोड़ 94 लाख 97 हजार 175 रुपए की फसल के नष्ट होने का आकलन किया गया है। इतनी ही राहत राशि इन किसानों को उपलब्ध कराने की अनुशंसा भी की गई है। इस सर्वे रिपोर्ट से कलेक्टर अरविंद दुबे ने भी शासन को अवगत करा दिया है। साथ ही किसानों को नुकसान की भरवाही के लिए यह राशि उपलब्ध कराने की डिमांड की है, ताकि मॉडिफाई किसानों को राहत राशि बांट कर उन्हें हुए नुकसान से कुछ राहत पहुंचाई जा सके।

धोबाखेड़ी के किसान भजनलाल मेहरा और नीलेश शर्मा ने बताया कि बेतवा नदी में आई बाढ़ के पानी ने उन्हें बर्बाद करके रख दिया है, उनकी पूरी फसल बाढ़ के पानी में चार-पांच तक डूबी रहने से पूरी तरह से खराब हो गई है। कर्ज लेकर उन्होंने धान लगाई थी। उनकी फसल बहुत अच्छी थी और उम्मीद थी कि तीन से चार लाख तक की फसल बिक जाती थी, लेकिन उनके अरमानों पर बाढ़ ने पानी फेर दिया। अब उन्हें मुआवजा ही कुछ राहत प्रदान कर सकता है, क्योंकि उनके पास रबी सीजन की बोवनी करने के लायक तक पैसे नहीं हैं। राहत राशि भी समय पर नहीं मिलती तो उन्हें फिर से कर्ज लेकर बोवनी करने को मजबूर होना पड़ेगा।

रायसेन-गौहरगंज में ज्यादा नुकसान

रायसेन और गौहरगंज के गांवों में बेतवा नदी में आई बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। रायसेन तहसील के सबसे ज्यादा 102 गांवों में 5851 किसानों की 7234.857 हेक्टेयर की फसल को नुकसान पहुंचा है। यहां के किसानों के लिए 10 करोड़ 73 लाख 87 हजार 421 रुपए की राहत राशि शासन से मांगी गई है। इसी तरह गौहरगंज के 67 गांवों में 2405 किसानों की 2170.109 हेक्टेयर की फसल को नुकसान पहुंचा है। यहां के किसानों को भी 3 करोड़ 52 लाख 96 हजार 113 रुपए की राहत राशि दिलाई जाएगी।

अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की सर्वे रिपोर्ट आ गई है। नुकसान के आकलन के आधार पर शासन से राहत राशि उपलब्ध कराने की डिमांड की गई है। शासन से राहत राशि प्राप्त होते ही किसानों के खेतों में डलवाई जाएगी। अरविंद दुबे, कलेक्टर, रायसेन

किसानों को जानकारी देते कृषि वैज्ञानिक डॉ. सिंह बोले

धान की उन्नत किस्म पर्यावरण का करती है संरक्षण



दरिया। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र पर संचालित जलवायु समुदायन कृषि में नवप्रवर्तन परियोजना के तहत ग्राम सनौरा में धान प्रक्षेत्र दिवस मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एके सिंह ने धान की उन्नत किस्म की प्रजाति पीबी 1509 के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि यह फसल पर्यावरण का संरक्षण करने में सहायक है। उन्होंने कहा कि, धान की यह प्रजाति हमारे जिले के लिए बहुत ही अनुकूल है। जिसका अच्छा प्रभाव देखने को मिला। उन्होंने कहा कि कम पानी होने पर भी धान की उन्नत प्रजाति को किसान भाई लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी अवधि 120 दिन होती है, जिससे किसानों की लगभग 3 सिंचाई के पानी की बचत होती है। साथ ही हानिकारक गैसों के उत्सर्जन कम होने के कारण इस प्रजाति के द्वारा पर्यावरण संरक्षण भी होता है। केंद्र के अन्य वैज्ञानिक डॉ. राजीव सिंह चौहान द्वारा किसानों को वर्षा जल संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने तालाब, चैक डेम, बोरी बंधन द्वारा जल संरक्षण की तकनीक के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के द्वारा आज बचाया गया जल आगे रबी की फसल में जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में काम आ सकता है। कार्यक्रम में ग्राम सनौरा सहित अन्य ग्रामों के लगभग आधा सैकड़ा से अधिक किसानों ने सहभागिता की। इस अवसर पर किसानों को उन्नत तकनीक के साथ-साथ धान में रोग और कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई।

प्रदेश में अब तक लंपी बीमारी से स्वस्थ हुए 9488 पशु

मध्यप्रदेश में साढ़े चार लाख पशुओं का हुआ टीकाकरण

भोपाल। जागत गांव हमार

राज्य गौ-संवर्धन बोर्ड की कार्य-परिषद के अध्यक्ष गिरि ने बताया कि राज्य शासन द्वारा गौ-धंस वंशीय पशुओं को लंपी रोग से बचाने के लिये हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गिरि जिलेवार गोशालाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उनको आवंटित जिलों में लगातार भ्रमण कर टीकाकरण, दवा की उपलब्धता, रोग की स्थिति आदि की स्थल पर जांच कर रहे हैं। अब तक प्रदेश के 4 लाख 44 हजार 687 गौ-धंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। वर्तमान में 30 जिलों के 3 हजार 174 गांव में गौ-धंस वंशीय पशु लंपी चर्मरोग से प्रभावित हैं। अब तक कुल 12 हजार 655 पशु लंपी रोग से प्रभावित हुए और इसमें से 9 हजार 488 स्वस्थ हो चुके हैं। पशुपालकों से अनुरोध किया गया है कि लक्षण दिखते ही निकटस्थ पशु औषधालय, पशु चिकित्सालय या भोपाल स्थित कंट्रोल-रूम में दूरभाष पर सूचना दें। तुरंत इलाज शुरू होने से पशु के जल्दी ठीक होने की संभावना रहती है। दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाती है, जो कुछ समय बाद ठीक हो जाती है।



हर जिले में गठित रेपिड रिस्पांस टीम

त्वरित इलाज पहुंचाने के लिए कलेक्टर के निर्देशन में प्रत्येक जिले में रेपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। टीम सूचना मिलते ही तुरंत सक्रिय हो जाती है। पशुपालन विभाग द्वारा लगातार टीकाकरण, स्वास्थ्य और जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। पशुपालकों को स्थानीय भाषा में भी जागरूक किया जा रहा है।

दुग्ध संघ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मध्य हुआ करार

दुधारू पशु खरीदने एसबीआई की चिन्हित शाखाएं देंगी ऋण

भोपाल। जागत गांव हमार

एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। इसमें दुग्ध संघों की वार्षिक सभाओं में बैंक के अधिकारी उपस्थित होकर पशु पालकों को पशु खरीदने के लिए ऋण दिलाने में सहायता करेंगे। प्रबंध संचालक स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तरुण राठी ने बताया कि दुग्ध संघों के कार्यक्षेत्र की समितियों के पात्र सदस्यों को त्रि-पक्षीय अनुबंध के तहत 2, 4, 6 और 8 दुधारू पशु खरीदने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में चयनित 3 से 4 बैंक शाखाओं द्वारा ऋण राशि उपलब्ध कराई जाएगी। हितग्राही को मार्जिन मनी के रूप में 10 प्रतिशत राशि जमा करनी

होगी। दस लाख रुपए तक का मुद्रा लोन बिना कोलेस्ट्रॉल एवं एक लाख 60 हजार रुपए का नान मुद्रा लोन बिना कोलेस्ट्रॉल त्रि-पक्षीय अनुबंध के तहत हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाएगा। हितग्राहियों को ऋण की अदायगी 36 किस्तों में करनी होगी। पात्र हितग्राही को निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन के साथ फोटो, आधार/पैनकार्ड, वोटर आईडी, दुग्ध समिति की सक्रिय सदस्यता का प्रमाण-पत्र और त्रि-पक्षीय अनुबंध आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे। हितग्राही को दुग्ध समिति में दूध प्रदाय करना अनिवार्य होगा। प्रति माह दूध की कुल राशि का 30 प्रतिशत भाग समिति द्वारा ऋण की अदायगी के लिए बैंक को भुगतान किया जाएगा।

अधिकारियों को दिए निर्देश

डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड होंगे



पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरदा का हुआ चयन

भोपाल। जागत गांव हमार

राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि राजस्व विभाग की सहायता से किसानों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए किसान क्रेडिट कार्ड के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण की पद्धति लागू की गई है। पद्धति के कम्प्यूटरीकरण से केसीसी ऋण देने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा, जो अधिक सुगम और किसानों के अनुकूल होगा। मंत्री ने बताया कि हरदा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया था। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों और अनुभव के

आधार पर इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। मंत्री राजपूत ने बताया कि इस पद्धति के लागू होने से किसानों को क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के लिए बैंक शाखा में जाने एवं किसी प्रकार के दस्तावेज को जमा करने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन ऑनलाइन एप से किए जा सकेंगे। साथ ही कृषि भूमि का सत्यापन भी ऑनलाइन हो जाता है। प्रकरण का अनुमोदन और संचितरण प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी होने से किसान त्वरित लोन प्राप्त कर सकते हैं।

यशोधरा ने की अमृत 2.0 योजना और जनसेवा अभियान की समीक्षा

शिवपुरी। जागत गांव हमार

मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी में अधिकारियों के साथ अमृत 2.0 योजना मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा की। इस अभियान के तहत 37 योजनाओं को चिन्हित किया गया है। जिस विभाग की जो योजना है उस में बेहतर प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी में अमृत 2.0 योजना के तहत 37 योजनाओं को चिन्हित किया गया है। जिस विभाग की जो योजना है उस में बेहतर प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी में अमृत 2.0 योजना के तहत 37 योजनाओं को चिन्हित किया गया है। जिस विभाग की जो योजना है उस में बेहतर प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि 31 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जा रहा है। तब तक संबंधित अधिकारियों का अवकाश नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है। इसमें रोजगार विभाग, उद्योग विभाग में सम्मन्वय हो। उद्योग विभाग द्वारा संचालित उद्यम क्रांति योजना की जानकारी ली। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के शिवपुरी क्षेत्र के अलग-अलग गांव में किए गए भ्रमण के दौरान प्राप्त समस्याओं के निराकरण की भी समीक्षा की, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण, हंडंपंप, विद्युत व्यवस्था, रोड, पीएम आवास, नल जल योजना आदि शामिल थे। बैठक के दौरान उन्होंने समीक्षा की और कई समस्याओं का निराकरण मौके पर ही करवाया।

रामो जाटव की कल्याणी पेंशन तुरंत स्वीकृत

बड़ागांव निवासी रामो जाटव की मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना स्वीकृति के संबंध में जिला पंचायत के सीईओ को निर्देश दिए और तत्काल पेंशन प्रकरण स्वीकृत कराया।

गांव में विद्युत व्यवस्था के निर्देश

शंकरपुर और केडर गांव में ग्रामीणों की लाइट की समस्या थी। यहां ट्रांसफार्मर खराब थे। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारी को तुरंत ट्रांसफार्मर ठीक कराकर विद्युत सुचारु करने के निर्देश दिए और कहा कि अभी ट्रांसफार्मर ठीक कराकर जानकारी दें।

विधायक निधि से बाड़ड़ीवाल के लिए दी राशि

नया खेड़ा गांव में बाड़ड़ीवाल निर्माण के लिए विधायक निधि से राशि दी जाएगी। इसके अलावा अन्य ग्राम पंचायतों में भी निमाज कायज के संबंध में ग्रामीण यात्रिकी सेवा विभाग के कार्यपालन यंत्रों को एक सप्ताह में डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए।

यह रहे उपस्थित

बैठक में लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, नवनिर्वाचित पाण्डे, कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

वैज्ञानिकों ने किसानों को तिल की उन्नत खेती की दी जानकारी

पन्ना। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना द्वारा अखिल भारतीय तिल एवं रामतिल परियोजना अंतर्गत ग्राम तिलगुवा में तिल की उन्नत किस्म टीकेजी 306 के प्रदर्शन कृषकों के यहां खरीफ 2022 में कृषि की विभिन्न तकनीकों जैसे, बीजोपचार, खरपतवार प्रबंधन, उन्नत किस्म बोनी का तरीका एवं संपूर्ण कृषि तकनीकों दिये गये थे। उपरोक्त प्रदर्शनों का भ्रमण कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ से आए पौध प्रजनक डॉ. शिवरतन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों डॉ. डी.आर मिश्रा, डॉ. बॉके

पाणी, डॉ. बीसी धीर एवं डॉ. सरिता द्वारा किया गया। भ्रमण के दौरान इनके द्वारा कृषकों को तिल की उन्नत किस्म के बारे में एवं तिल की फसल में बीजोपचार पौध संख्या एवं संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई साथ ही कृषकों के द्वारा भी इनके अनुभव को साझा दिया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र, पन्ना के प्रमुख डॉ. पीएन त्रिपाठी एवं रितेश बागोर कार्यक्रम सहायक सहित तिलगुवा के प्रगतिशील कृषक राजभान सिंह एवं ज्ञान सिंह यादव भी उपस्थित थे।

75 हजार हेक्टेयर गेहूं, 60 हजार हेक्टेयर में होगी सरसों की बोवनी कृषि विभाग ने तय किया रबी फसलों की बोवनी का लक्ष्य

शिवपुरी,रघोपुर। खेब तज मौर्य

खरीफ फसलों की कटाई के बीच जिले के किसान रबी फसलों की तैयारियों में जुट गए हैं। कृषि विभाग ने भी रबी फसलों की बोवनी का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। इस बार एक लाख 68 हजार हेक्टेयर में रबी फसलों की बोवनी की जाएगी। इस दौरान 75 हजार हेक्टेयर में जहां गेहूं की बोवनी की जाएगी। वहीं 60 हजार हेक्टेयर में सरसों की बोवनी होगी। लक्ष्य तय करने के बाद कृषि विभाग का अमला लक्ष्य की पूर्ति की कार्रवाई में जुट गया है। कृषि विभाग ने रबी सीजन 2022-23 के लिए फसलों की बोवनी का जो लक्ष्य तय किया है, उसके मुताबिक इस बार जिले में 1 लाख 68 हजार हेक्टेयर में रबी बोवनी की बोवनी होगी। जो गत वर्ष के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि गत वर्ष रबी सीजन का रकबा 1 लाख 66 हजार हेक्टेयर तय किया गया था इस दफा का लक्ष्य सबसे ज्यादा है, क्योंकि इतना लक्ष्य कभी लिया गया नहीं है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार बारिश भी निर्धारित कोटे से ज्यादा हो गई है। वहीं चंबल नहर से भी अच्छा पानी मिलने की उम्मीद है। इसलिए इस बार फसल की बोवनी का लक्ष्य बढ़ाकर लिया गया है। उधर किसान भी अच्छी फसल की उम्मीद में रबी फसलों की तैयारियों में जुट गए हैं।

गेहूं का घटाया रकबा

कृषि विभाग ने सरसों का रकबा बढ़ाकर तो गेहूं का रकबा घटाकर लिया है। बताया गया है कि सरसों की बोवनी का रकबा 60 हजार हेक्टेयर तय किया गया है। गत वर्ष सरसों की बोवनी का रकबा 57 हजार तय किया था। जबकि गेहूं की बोवनी का लक्ष्य गत वर्ष 77 हजार हेक्टेयर तय किया था, जो कि 75 हजार हेक्टेयर तय किया है। चना के लिए 30 हजार हेक्टेयर का रकबा निर्धारित किया है। जबकि गन्ना, मूएर, मटर, अलसी आदि फसलों की बोवनी के लिए थोड़ा-थोड़ा रकबा तय किया है। जिले में रबी सीजन की फसले मुख्य मानी जाती है। इसलिए कृषि विभाग का अमला रबी फसलों की बोवनी का लक्ष्य निर्धारित करने के बाद लक्ष्य पूर्ति की कार्रवाई में जुट गया है, वहीं किसान भी फसलों की बोवनी के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि अभी खरीफ फसलों की कटाई पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए किसान फसल की कटाई में जुटे हुए हैं।

इस बार 1 लाख 68 हजार हेक्टेयर में रबी फसलों की बोवनी का लक्ष्य तय किया है, जो सर्वाधिक है, क्योंकि इतना लक्ष्य अभी तक कभी लिया नहीं गया था। चूंकि बारिश अच्छी हुई है, इसलिए हमने बोवनी का लक्ष्य बढ़ाकर लिया है। पी गुजरे, उप संचालक, कृषि विभाग रघोपुर



किसान अपने खेत पर स्वयं बीज उत्पादन कर अनावश्यक खर्च से बचें: डॉ. भदौरिया

भिंड। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र लहार द्वारा ग्राम उद्योतपुरा में तिलहन क्लस्टर अग्रिम पॉक प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रखेत्र दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें कृषि वैज्ञानिकों के साथ गांव के किसानों ने भाग लिया एवं वैज्ञानिकों के साथ किसानों के तिल प्रदर्शनों का भ्रमण भी किया गया।

कार्यक्रम के दौरान डॉ. अवधेश सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कृषि प्रखेत्र पर उत्पादित किस्मों की बीजदर एवं उत्पादन के बारे में जानकारी दी। डॉ. रूपेन्द्र कुमार द्वारा फसलों के बारे में अन्य जानकारी के बारे में अवगत कराया साथ ही प्राकृतिक खेती के बारे में भी जानकारी दी। वैज्ञानिक दीपेन्द्र शर्मा (मृदा

विज्ञान) द्वारा विभिन्न फसलों में संतुलित उर्वरक एवं मृदा नमूना लेने की विस्तृत जानकारी दी। डॉ. एन. एस. भदौरिया, वैज्ञानिक (पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी) द्वारा सरसों, चना, गेहूं की विभिन्न किस्मों के गुणों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया कि बीज को बोने से पूर्व बीजों का अंकुरण परीक्षण किए जाने पर जोर दिया तथा अंकुरण की विभिन्न विधियों के बारे में बताया। डॉ. भदौरिया द्वारा कृषक अपने खेत पर शुद्ध बीज उत्पादन कैसे किया जाता है कि विज्ञान के बारे में जानकारी दी। कृषक यदि खुद का बीज उत्पादन करता है तो समय के साथ साथ बीज के साथ होने वाले व्यय को भी कम कर सकता है।

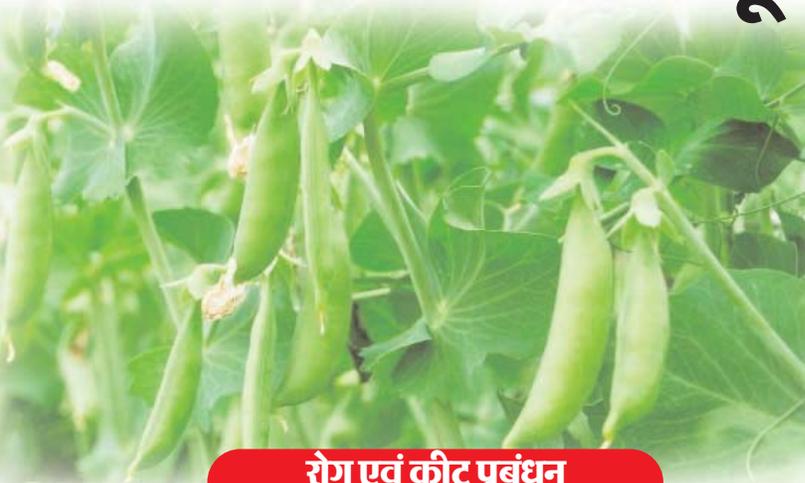
मटर रबी सीजन की प्रमुख दलहनी फसल

मटर की खेती से कमाए भरपूर लाभ

टीकमगढ़। जगत गांव हमार

मटर की खेती पूरे भारत में व्यावसायिक रूप से की जाती है। मटर रबी मौसम की प्रमुख दलहनी फसल है। मटर का सब्जियों में एक खास स्थान है। इसकी खेती हरी फली और दाल प्राप्त करने के लिए की जाती है। मटर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, रेशा, और विटामिन जैसे मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी तत्व हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं। मटर कि खेती भूमि की उर्वरा शक्ति में भी उपयोगी है। मटर की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, फिर भी मैदानी भागों की बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी गई है। मटर के लिए भूमि को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। खरीफकी फसल की कटाई के बाद भूमि की जुताई डिस्क हैरो के साथ ही 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर जुताई करके पाटा लगाकर को समतल एवं भरभुरा तैयार कर लेना चाहिये। धान के खेतों में मिट्टी के ढेलों को तोड़ने हेतु रोटावेटर प्रयोग करना चाहिए। अच्छे अंकुरण के लिए मिट्टी में नमी होना जरूरी है।

राजोबियम संवर्धक (कल्चर) से बीजों को उपचारित करना उत्पादन बढ़ाने का सबसे सरल साधन है। दलहनी फसलों में वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने की क्षमता जड़ों में स्थित ग्रंथिकाओं की संख्या पर निर्भर करती है और यह भी राजोबियम की संख्या पर भी निर्भर करता है। इसलिए इन जीवाणुओं का मिट्टी में होना आवश्यक है। क्योंकि मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए राईजोबियम संवर्धक से बीजों को उपचारित करना आवश्यक होता है। राईजोबियम से बीजों को उपचारित करने के लिए 10 मिली प्रति किग्रा. बीज की डर से उपचारित करना चाहिए। बीजों को उपचारित करने के लिए 50 ग्राम गुड़ को एक लीटर पानी में घोल कर गर्म करके मिश्रण तैयार करना चाहिए। सामान्य तापमान पर उसे ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद उसमें एक पैकेट कल्चर डालें और अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण में बीजों को डालकर अच्छी तरह से मिलाएं, जिससे बीज के चारों तरफ कल्चर का पतल लग जाय। बीजों को छाया में सुखाएं और फिर बोयें। क्योंकि राईजोबियम कल्चर फसल विशेष के लिए ही होता है, इसलिए मटर के लिए संस्तुत राईजोबियम का ही प्रयोग करना चाहिए।



रोग एवं कीट प्रबंधन

खरपतवार नियंत्रण खरपतवार फसल के निमित्त पोषक तत्वों व जल को ग्रहण कर फसल को कमजोर कर देता है और उपज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों से अधिक हानि होती है। अगर इस दौरान खरपतवार खेत से नहीं निकाले गए तो फसल की उत्पादकता प्रभावित होती है। यदि खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जैसे- बधुआ, संजी, कृष्णनील, सतपती अधिक हों तो 4-5 लीटर स्टाम्पा - 30 (पैडीमिथेलेन) 600-800 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से घोलकर बोवनी के 72 घंटे के अंदर छिड़काव कर देना चाहिए। इससे काफी हद तक खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है।

रुआ इस रोग के कारण जमीन के ऊपर के पौधे के सभी अंगों पर हल्के से चमकदार पीले (हल्दी के रंग के) फफोले नजर आते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर ये ज्यादा होते हैं। जिसमें रोग-ग्रस्त पत्तियां मुरझा कर गिर जाती हैं। अंत में पौधा सुखकर मर जाता है। अंग्रेठी फसल बोने से रोग का असर कम होता है। फसल चक्र अपनाना चाहिए। रोगरोधी किस्मे जैसे हंस, अर्का अजीत आदि का चयन करना चाहिए। खड़ी फसल में रोग का प्रकोप होने पर शुलभशील गंधक (3 ग्राम) या कार्बेन्डाजिम (1 ग्राम) प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल में 2 बार छिड़काव करना चाहिए या सल्फर पाउडर 25 किग्रा राख के साथ मिश्रण करके प्रति हेक्टेयर भुरकाव करना चाहिए।

आर्द्र जड़ गलन इस रोग से प्रकोपित पौधों की निचली पत्तियां हल्के पीले रंग की हो जाती हैं। पत्तियां नीचे की ओर मुड़कर पीली पड़कर सूख जाती हैं। तनों और जड़ों पर खुरदरे खुरदरे से पड़ जाते हैं। यह रोग जड़-तंत्र को सड़ा डालता है। यह रोग मृदा जनित है। रोग के बीजाणु वर्षों तक मिट्टी में जमे रहते हैं। हवा में 25 से 50 : की अपेक्षित आर्द्रता और 22 से 32 डिग्री सेल्सियस दिन के अंतराल में 2 बार छिड़काव करना चाहिए या सल्फर पाउडर 25 किग्रा राख के साथ मिश्रण करके प्रति हेक्टेयर भुरकाव करना चाहिए।

चूर्णिल आसिता रोग इस रोग से पत्तियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं और बाद में तनों और फली पर भी असर होता है। पत्तियों की दोनों सतह पर सफेद धब्बे बनते हैं। पहले छोटी-छोटी गंहीन धब्बे या चित्तियों के रूप में बनते हैं लेकिन बाद में इनके चारों ओर चूर्णी समूह फैल जाता है। रोगी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की कमी हो जाती है। पौधे छोटे रह जाते हैं और उन पर फलियां भी कम और हल्की लगती हैं। पत्तियों के जिस स्थान पर परजीवी का कवक जाल फैला रहता है, वहां की कोशिकाएं ऊतक क्षय की वजह से मर जाती हैं। चूर्णिल आसिता रोग की रोकथाम के लिए रोग के प्रकोप के शुरुआत में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या सल्फर 80 : डेल्क्यूजी 750-1000 ग्राम प्रति एकड़ 300-400 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

बोवनी का समय-

मटर की बोवनी मध्य अक्टूबर से नवम्बर तक की जाती है जो खरीफ की फसल की कटाई पर निर्भर करती है। फिर भी बोवनी का उपयुक्त समय अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से नवम्बर का प्रथम सप्ताह है।

बीज-दर, दूरी - बोवनी-

बीजों के आकार और बोवनी के समय के अनुसार बीज दर अलग-अलग हो सकती है। समय पर बोवनी के लिए 75-80 किग्रा. बीज प्रति हे. पर्याप्त होता है। पछेती बोवनी में 100-110 किग्रा. प्रति हे. बीज होना चाहिए। सोड ड्रिल से 30 सेंमी की दूरी पर बोवनी करनी चाहिए। बीज की गहराई 5-7 सेंमी. रखनी चाहिए जो मिट्टी की नमी पर निर्भर करती है।

उर्वरक-

मटर में सामान्यतः 20 किग्रा, नाइट्रोजन एवं 60 किग्रा. फास्फोरस बोवनी के समय देना पर्याप्त होता है। इसके लिए 100-125 किग्रा. डाईअमोनियम फास्फेट (डी, ए पी) प्रति हेक्टेयर दिया जा सकता है। अर्थात् यूरिया 40-42 किग्रा और सिंगल सुपर फास्फेट 375 किग्रा प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। पोटेशियम की कमी वाले क्षेत्रों में 20 किग्रा पोटाश (स्यूरेट ऑफपोटाश के माध्यम से) दिया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में गंधक की कमी हो वहां बोवनी के समय गंधक भी देना चाहिए।

सिंचाई-

प्रारंभ में मिट्टी में नमी और शीत ऋतु वर्षा के आधार पर 1-2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल की पहली सिंचाई फूल आने से पूर्व और दूसरी सिंचाई फलियां बनने के समय करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हल्की सिंचाई करें और फसल में पानी उहसाव न रहे।

पीला मोजेक वायरस से मध्यम प्रतिरोधक क्षमता

इंदौर के सोयाबीन संस्थान की तीन किस्मों उच्च समिति द्वारा अनुमोदित

इंदौर। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर द्वारा विगत कुछ वर्षों से लगातार नई-नई किस्मों का विकास किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में संस्थान द्वारा विकसित तीन किस्मों एनआरसी 157, एनआरसी 131 एवं एनआरसी 136 को राज्य स्तरीय उच्च समिति द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए अनुमोदित किया गया है।

इस बारे में संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रजनक डॉ. संजय गुप्ता ने बताया कि एनआरसी 157 (आईएस 157) एक मध्यम अवधि में पकने वाली किस्म है, जो मात्र 94 दिनों में पक जाती है, जिसकी औसत उपज 16.5 किंटल प्रति हेक्टेयर है तथा यह अक्टूबरिया लीफ स्पॉट, बेक्टेरियल पस्तुलस एवं टारगेट लीफस्पॉट जैसी बीमारियों से मध्यम प्रतिरोधी भी है। संस्थान के परीक्षणों में पाया गया है कि एनआरसी 157 की दर से बुआई (20 जुलाई तक) करने से भी न्यूनतम



उपज का नुकसान होता है। उनके द्वारा विकसित एक अन्य किस्म एनआरसी 131 (आईएस131) के बारे में डॉ. गुप्ता ने बताया कि यह 93 दिनों की मध्यम अवधि में पकने वाली किस्म है, जिसकी औसत उपज 15 किंटल प्रति हेक्टेयर है। कारकोल रोट एवं टारगेट लीफ स्पॉट जैसे रोगों से मध्यम प्रतिरोधक है। संस्थान द्वारा देश के पूर्वी क्षेत्र के लिए पहले से ही विकसित एवं अनुशासित किस्म एनआरसी 136 (आईएस 136) को भी इस वर्ष मध्य प्रदेश में खेती के लिए अनुमोदित किया गया है। इस किस्म के प्रजनक तथा संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. ज्ञानेश कुमार सातपुरे ने बताया कि एनआरसी 136 किस्म 105 दिनों में पकती है। इसकी औसत उपज 17 किंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म पीला मोजेक वायरस से मध्यम प्रतिरोधक क्षमता रखती है। भारत की पहली सुखा सहिष्णु किस्म है।

किसान उत्पादक संगठनों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

पत्ता। जगत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना में किसान उत्पादक संगठनों की एक दिवसीय कार्यशाला रिलायंस फाउण्डेशन एवं कृषि विज्ञान केन्द्र, पन्ना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुई, जिसमें सहायक महाप्रबंधक नाबार्ड (जिला विकास) एम धानेश एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. पीएन त्रिपाठी की उपस्थिति रही।

कार्यशाला में जिले के बीजोत्पादक संस्था तथा किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सहायक महाप्रबंधक नाबार्ड द्वारा जिले में नये किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए आवश्यक जानकारी दी गई, जिससे किसान आत्मनिर्भर बन सके एवं जिले की एक नई पहचान स्थापित हो सके। एक जिला एक उत्पादक अंतर्गत आंवले के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में बीजोत्पादक संस्था एवं किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी आवश्यक सुझाव प्राप्त हुए जिससे किसानों की लागत कम एवं आमदनी बढ़ सके।

कार्यशाला में पौध संरक्षण वैज्ञानिक डॉ. आरके जायसवाल ने वर्तमान में खरीफ फसलों में कीट व्याधि एवं बीमारियों की रोकथाम के विषय में तकनीकी व्याख्यान दिया। बीज प्रमाणीकरण संस्था से दिनेश कुमार खाखरे एवं डॉ. आशा सिंह, सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा अच्छी गुणवत्तायुक्त बीजोत्पादन हेतु ध्यान रखने योग्य सावधानियों के बारे में बताया। रिलायंस फाउंडेशन से संतोष सिंह द्वारा जिले के चयनित ग्रामों में संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में सहायक संचालक कृषि उत्तम सिंह बागरी, कृषि वैज्ञानिक रितेश बागरी, प्रक्रिया प्रभारी मप्र योगेन्द्र नायक, मप्र राज्य आजीविका मिशन से सुशील शर्मा रिलायंस फाउंडेशन से नीरज कुशवाहा, भाग्यश्री सिंह, प्रवीण तिवारी तथा बीजोत्पादन संस्था/किसान उत्पादन संगठन के प्रतिनिधि तथा प्रतिशाली कृषक उपस्थित हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉ. आरपी सिंह एवं आभार प्रदर्शन रितेश बागरी द्वारा किया गया।



सीहोर, विदिशा और रायसेन से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत

ग्राम पंचायत तालपुरा में खुलेगी नवीन उचित मूल्य की दुकान

डेयरी प्लस योजना का शिवराज ने किया शुभारंभ



समस्याओं के शत प्रतिशत निराकरण का निर्देश

भोपाल। जागत गांव हमार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विकासखंड की ग्राम पंचायत तालपुरा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने आवेदकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना और आवेदनों का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र एवं सामग्री का प्रतीक स्वरूप वितरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर आमजनों को योजनाओं से लाभांशित करने के लिए ही लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों से सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिले, इसके लिए विशेष शिविर लगायें। मुख्यमंत्री ने जन सेवा अभियान शिविर में विभिन्न योजनाओं से लाभांशित हितग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। सीएम चौहान ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ भी किया। उन्होंने चिन्तित हितग्राहियों से संवाद कर उनके पशुपालन व्यवसाय के संबंध में जानकारी प्राप्त की। योजना में हितग्राहियों को दो मुरां भैंस प्रदाय की गई हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना से लाभांशित हितग्राही कमल किशोर पंवार, राकेश कटारे, राहिलकिशोर अहिरवार सहित अन्य पशुपालकों से संवाद कर उनका हालचाल जाना और उनके व्यवसाय की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने शिविर में लाभांशित हितग्राहियों से भी संवाद कर योजना के लाभ प्राप्ति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मंच पर प्रश्नोत्तरी संवाद कर शिविर में आए आवेदनों के निराकरण तथा योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों के बारे में भी जाना।

मुख्यमंत्री चौहान ने तालपुरा सहित अन्य चार ग्राम पंचायतों में विशेष राजस्व शिविर लगा कर राजस्व संबंधी प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत तालपुरा में नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों को लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें। सीहोर जिले के प्रभारी और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पशुपालन सामाजिक न्याय एवं निःशकन कल्याण मंत्री प्रेमसिंह पटेल, लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योग मंत्री ओमप्रकाश सखलेका, सांसद रमाकान्त भार्गव सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

यथा है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना

डेयरी व्यवसाय से प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि हो और वे पशुपालन कर अधिक से अधिक आय अर्जित कर सकें, इसके लिए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना प्रदेश के तीन जिलों सीहोर, विदिशा और रायसेन में शुरू की गई है। पहले से ही पशुपालन का कायज कर रहे पशुपालकों को मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में दो मुरां भैंसे उपलब्ध कराई जा रही है। इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता 10 लीटर प्रतिदिन की होती है। मुरां भैंसों की लागत दो लाख 50 हजार रुपए होगी। योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुपालकों को राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान एवं पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुपालकों को अंशदान के रूप में 62 हजार 500 रुपए तथा पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी वालों को एक लाख 50 हजार रुपए जमा करने होंगे। इसमें पशुपालकों के आने-जाने का व्यय एवं बीमा आदि की राशि भी शामिल है।

इंदौर में हुई राज्य स्तरीय कार्य कृषि अवसंरचना निधि कार्यशाला

कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में मप्र अक्वल

भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि कृषि अवसंरचना निधि (आईएएफ) के उपयोग में मध्यप्रदेश पूरे देश में अक्वल है। इस योजना से किसानों को अधो-संरचनात्मक विकास के लिए अनुदान युक्त ऋण दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की पहल से खेती के लिए आधारभूत संरचना का विकास निरंतर हो रहा है। कृषि मंत्री कृषि अवसंरचना निधि संबंधी इंदौर में हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला को वचुअली संबोधित कर रहे थे। इंदौर कृषि महाविद्यालय के डीन डॉ. शरद चौधरी सहित अन्य अधिकारी एवं इंदौर-उज्जैन संभाग के कृषक एवं स्व-सहायता समूह, बीज उत्पादक समितियों सहित कृषि उद्यमियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कृषि मंत्री ने बताया कि देश में कृषि अवसंरचना में सुधार को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआयएफ) स्कीम का संचालन किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा अवसंरचना के लिए एक लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया गया है, जिसमें प्रदेश को 7 हजार 440 करोड़ रुपए से 12 हजार करोड़ रुपए तक की वित्तीय सुविधा मिलनी है। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि योजना के द्वारा जो भी कृषक, कृषि से जुड़े उद्यमी, कृषि उत्पादकता समूह, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह, बैंक सहित कृषि से जुड़े लोग कृषि अधो-संरचना निर्माण के लिए बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज छूट 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।



तीन प्रतिशत का ब्याज दिया जाता है अनुदान

कृषि मंत्री ने बताया कि एआयएफ फंड से वित्तीय सहायता कोल्ड स्टोर एवं कोल्ड चेन देयर हाउस, सायलोजी, पैक हाउस, विश्लेषण/जांच इकाई, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट, लॉजिस्टिक्स सुविधा, ई-मार्केटिंग, राईपनिंग चेंबर, जैव उत्प्रेरक उत्पादन इकाई के निर्माण, स्मार्ट एवं प्रिंसीपल फार्मिंग इत्यादि के लिए प्रदान की जा रही है। इंदौर संभाग में बैंकों द्वारा 126 आवेदनों में 123 करोड़ 19 लाख की राशि का सत्यापन हो चुका है। इन आवेदनों में बैंकों द्वारा 77 करोड़ 18 लाख का वितरण किया जा चुका है। योजना प्रदेश में कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में एक अहम भूमिका निभा रही है। मंडी बोर्ड की एमडी जीसी रश्मि ने बताया कि योजना में 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाता है। केंद्र द्वारा क्रेडिट गारंटी दी जाती है। योजना में देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के क्रम को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता के लिए फसलोपरांत प्रबंधन और खेती संबंधित निवेश के लिए उद्युक्त ऋण सुविधा भी दी जाएगी।

जवाहरलाल नेहरू कृषि वि.वि. का 59वां स्थापना दिवस समारोह

मप्र को कृषि में अग्रणी बनाने में वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका: नरेंद्र सिंह तोमर

भोपाल। मध्यप्रदेश को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के 59 वें स्थापना दिवस समारोह को वचुअली संबोधित करते हुए यह बात कही। प्रदेश के किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने वचुअली संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश में किसानों को लाभांशित करने के समग्र प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि आज मप्र खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। इसकी बुनियाद में कृषि विवि, कृषि विज्ञान केंद्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की किसान कल्याणकारी योजनाओं का प्रदेश में सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में भी प्राकृतिक और जैविक खेती विभाग गठित करेंगे।

विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिए गए पुरस्कार

स्थापना दिवस समारोह में लाईफटाइम अचीवमेंट अवार्ड-2022 डॉ. चंद्रकांत टेकचंदानी एवं अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी संकाय जनकृषि वि.वि. जबलपुर, जनकृषि वि. रटार एल्युमिनस सम्मान जवाहर रत्न अवार्ड 2022 डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी एवं उप महानिदेशक शिक्षा एवं स्वास्थ्य विज्ञान आईसीआर, डॉ. दिनेश कुमार मारोटिया एवं अध्यक्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय एवं डॉ. पवन कुमार अहिरवार जिला पंजीयक एवं कलेक्टर इंदौर, कृषक फैलो सम्मान-2022 वसुंधरा जयंत मेहता दमोह, ओम ठाकुर सिवनी, सुमित चौरसिया पन्ना और आशीष कुमार जायसवाल जिला सिवनी को प्रदान किया गया। उत्कृष्ट आदिवासी महिला कृषक सम्मान -2022 सौनिया आदिवासी जिला रीवा, रामाबाई आदिवासी जिला टीकमगढ़, दुगाबजाई जिला धार को दिया गया।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 9425048589

“आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा”